MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

(b) There is no delay in decision-making and no case of any management tendering their resignation has come *to* notice.

(c) Does not arise.

Recession in core-sector

433. SHRI KAMAL MORARKA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of the core sectors still suffering from the recessionary trends;

(b) whether Government have mads any study of factors behind the recessionary trends in these segments;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the details of the action taken by *Government to save these industries from* recession?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (d) A statement showing the rates of growth in the core infrastructure sectors during April-December 1992, over April-December, 1991, is enclosed (see below). All the sectors other than phosphatic fertilizers and crude oil have registered an increase in output during this period. The shortfall in production of phosphatic fertilizer has been due to both demand and supply constraints. Some SSP units have suffered from liquidity problems and from shortage of imported phosphoric acid. Increase in prices has contributed to fall in demand. However, the production of nitrogenous fertilizer has shown positive growth.

Some operational problems led to lower output in the crude oil sector. Sectors like steel and cement though showing positive growth have faced demand constraints due to lower off-take, lower Government spending, high input cost, etc.

High priority has been accorded to the core sector as incorporated in the programmes and policies announced in the Eighth Five Year Plan. Initiatives taken in the new Industrial Policy, in the Union Budget 1992-93 and in the Export & Import Policy, 1992-97, and thereafter are aimed at accelerating overall industrial production. This will provide stimulus to the production in the core sector industries also.

Statement

S.No.	Industry	% Growth rate (Apr.-Dec., 92) (Apr.-Dec 91)
1.	Power Generation	4.6
2.	Coal	2.9
3.	Saleable Steel	4.5
4.	Fertilizers (N2)	2.4
5.	Fertilizers (P205)	−7.5
6.	Cement	0.7
7.	Crude Oil	−10.8
8.	Petroleum Refinery Products	7.5
9.	Telecommunication (Telephone instruments)	24.2

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विकास

434. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने पिछले वर्ष की तुलना में कम विकास कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपक्रमों में विकास कार्य में कमी होने के क्या कारण हैं?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) विभिन्न सरकारी उद्यमों द्वारा समय-समय पर उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। बहरहाल, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों का

पंजीकृत कार्यालय गुजरात राज्य में स्थित है, उनमें से प्रत्येक में विगत तीन वर्ष के दौरान विस्तार, विकास एवं प्रतिस्थापन पर किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:

लाख रुपयों में

क्रम सं॰	सरकारी उद्यम का नाम	1990-91	1989-90	1988-89
1.	इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स लि॰	34472	34876	35194
2	एन्टीसी (गुजरात) लि॰	68	40	13

सरकारी उद्यमों में विकासात्मक कार्य संबंधी निर्णय परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता के साथ-साथ देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखकर किए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यकुशलता

435. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी निवेश में कमी आई है;

(ख) क्या इन उपक्रमों में निवेश में कमी के परिणामस्वरूप उनकी कार्यकुशलता और लाभ में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सरकारी उपक्रमों की कार्यकुशलता और लाभ को और अधिक बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 17 ऐसे उपक्रम हैं जिनके पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। विगत तीन वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक उद्यम में किए गए पूंजीनिवेश तथा उनके निवल लाभ/हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)।

(घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग एवं उद्यम द्वारा उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	निवल लाभ/हानि			पूंजी निवेश		
	1990-91	1989-90	1988-89	1990-91	1989-90	1988-89
आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यु॰ कारपो॰ आफ इण्डिया	233	166	193	1480	1364	1261
भारत इम्युलाजिकल एंड बायोलाजिकल्स कारपो॰ लि॰	20			1071	663	210
भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड	141	82	51	806	709	564
भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रैशर्स लिमिटेड	259	919	2616	5912	5642	5364
भारत यन्त्र निगम लिमिटेड	0	1	1	683	526	142
ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड	1566	1566	180	11937	11961	11334
ब्युलवेयर लिमिटेड	2	2	0	3	3	3
कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड	452	362	505	1681	1181	720
एल्गिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड	3527	3062	3107	8889	7839	6789
इण्डियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल्स कारपो॰ लि॰	14	10	17	85	85	99
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	137	129	23	781	644	508
नेप्टे॰ का (उत्तर प्रदेश) लिमिटेड	3287	2948	3048	25221	22516	20143
स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड	4825	4289	3721	11665	9963	8659
टेनरी एंड फुटवीयर कारपो॰ आफ इंडिया लिमिटेड	1870	1610	1404	6595	6040	5505
त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	361	442	282	2965	2735	2411
उत्तर प्रदेश ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	129	128	47	99	86	87
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	104830	162384	160158	701925	609065	501682